विधान परिषद • मंत्री-एमएलसी में गालीगलौज, मारपीट की नौबत

सदन की भाषा सड़क जैसी

मंत्री अशोक चौधरी और राजद एमएलसी सुनील सिंह के बीच भिड़ंत

एक उदाहरण देखिए... अशोक ने सुनील को चोट्टा कहा, तो सुनील ने चोर

सदन में अशोक और सुनील ने एक-दूसरे को अपशब्द बोले। अशोक ने कहा- चोट्टा हो। तुम्हारी औकात क्या है? इस पर सुनील बोले- तुम घोटालेबाज हो। चोर हो। दोनों में हाथापाई शुरू होती इससे पहले मार्शल आ गए।

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

बिहार के उच्च सदन, विधान परिषद में मंगलवार को जमकर गाली-गलौज हुई। हालात इतने बिगड़े कि मारपीट की नौबत आ गई। मार्शल ने बीच-बचाव कर हाथापाई रोकी। सदन की स्थिति बिगड़ते देख सभापति अवधेश नारायण सिंह ने तमाम विपक्षी विधान पार्षदों को दिन भर के लिए बाहर करा दिया। उन्होंने मार्शल से कहा- इन सबको पकड़कर बाहर निकालो। इसके बाद मार्शल विपक्षी सदस्यों को बाहर ले गए।

विपक्ष के सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और राजद के सुनील कुमार सिंह आमने-सामने आ गए। दोनों ने एक-दूसरे पर चोर-चोट्टा कहने का आरोप लगाया। -शेष पेज 15 पर

नीतीश गरिमा भूले : राबड़ी

राबड़ी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद की गरिमा भूल गए हैं। उन्होंने कहा- वे हमेशा लड़का-लड़की की भाषा बोलते हैं। सीएम माफी मांगे।

सदन में दैनिक भास्कर की प्रतियां लहराईं

सोशल मीडिया पर... बुड़ढ़ा लड़का लोफर है से फेल कमांडर तक

▪ **राजद की पोस्ट :** संवैधानिक पद पर बैठकर महिलाओं के लिए अश्लील बातें करने वाले बिहार का 'बुड़ढ़ा लड़का' लोफर है। उनको तुरंत कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बिहार लगातार शर्मसार हो रहा है।

▪ **जदयू की पोस्ट :** जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पोस्ट किया- जयचंद का सवाल आने पर न तो बदले हुए किडनी वाले की आवाज निकलती है, न ही हारे हुए भगोड़ा योद्धा की अक्ल काम करती है। फेल कमांडर के पास सिर्फ अपशब्द है।

कैसे बिगड़ा माहौल

▪ सदन की कार्यवाही तय समय से 15 मिनट देर से, 12.15 बजे शुरू हुई। विपक्ष के सभी विधान पार्षद 12 बजे ही अपनी सीटों पर बैठ गए थे। सत्ता पक्ष 12.15 बजे सदन में पहुंचा।

▪ कार्यवाही शुरू होते ही अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा-बगैर सूचना के सदन 15 मिनट देर से शुरू हुआ। सभापति ने कहा- यह हमारा विशेषाधिकार है।

▪ सिद्दीकी ने कहा-सोमवार को राबड़ी देवी के साथ मुख्यमंत्री का अभद्र व्यवहार हुआ। सत्ता पक्ष खेद व्यक्त करे। सभापति ने कहा- मामले की जांच हो रही है। फुटेज देखेंगे।

▪ अशोक चौधरी ने कहा- बगैर घंटी बजे सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। इसके बाद विपक्ष वेल में आ गया और नारेबाजी शुरू कर दी।

▪ इसी दौरान अशोक चौधरी और सुनील कुमार सिंह के बीच तू-तू, मैं-मैं और गाली-गलौज शुरू हो गई। मार्शल ने हाथापाई रोकी।

शाह-गडकरी की राह पर चले भाजपा अध्यक्ष

विधायक के रूप में सदन पहुंचे नितिन

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को जब बिहार विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुए, तो उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। नितिन नवीन अब अमित शाह और नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेताओं की उस विशेष श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने राज्य विधानमंडल का सदस्य रहते हुए पार्टी के शीर्ष पद की जिम्मेदारी संभाली है। इससे पहले अमित शाह 2014 से 2017 तक गुजरात के विधायक रहते हुए और नितिन गडकरी 2010 से 2013 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) रहते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे।

20 साल के अपने विधायी सफर को याद करते हुए नितिन नवीन ने कहा, "इस सदन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। भले ही पार्टी ने अब मेरी भूमिका बदल दी है, लेकिन बिहार के विकास के प्रति मेरी प्रतिबद्धता पहले जैसी ही रहेगी।" उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन और पीएम मोदी के सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि 2005 के बाद बिहार की छवि पूरी दुनिया में बदली है। उन्होंने संकल्प लिया कि 2047 तक 'विकसित बिहार' बनाने के सपने को पूरा करने के लिए वे अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे।

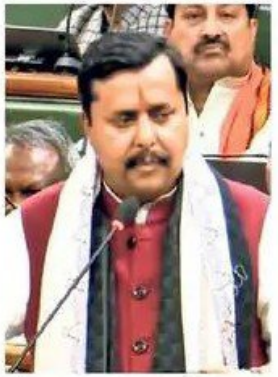

सीएम सदन में नहीं आए, विजय बोले- भाजपा के साथ बिहार भी चमक रहा

नितिन शून्यकाल के बाद 12:10 में सदन में पहुंचे। दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी उन्हें सदन में लेकर पहुंचे। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार सदन में नहीं आए। नितिन सीएम से उनके कमरे में जाकर मिले। सदन में विजय चौधरी ने कहा कि भाजपा का नेतृत्व चमक रहा है, बिहार भी चमक रहा है। स्पीकर प्रेम कुमार बोले- ये उपलब्धि उनकी प्रतिभा का परिचायक है। संजय सरावगी ने कहा कि इनके नेतृत्व में बंगाल, तमिलनाडु और केरल में भी भाजपा सरकार बनाएगी।

विपक्ष ने लोस अध्यक्ष के विरुद्ध चला अविश्वास प्रस्ताव का अस्त्र

विपक्ष के 120 सदस्यों ने किए नोटिस पर हस्ताक्षर, बताए अविश्वास प्रस्ताव लाने के चार कारण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बिरला ने नोटिस पर फैसला होने तक लोकसभा का संचालन नहीं करने का किया फैसला
- अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को आगे की प्रक्रिया के लिए लोकसभा सचिवालय को भेजा

सोमवार को सदन की कार्यवाही का संचालन करते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। फाइल/पेज >>

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर पक्षपात से लेकर विपक्षी महिला सांसदों को झूठे आरोपों के जरिये बदनाम करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने उनके विरुद्ध मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। इसमें प्रस्ताव लाने के चार कारण बताए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर आइएनडीआइए में शामिल सभी विपक्षी दलों के करीब 120 लोकसभा सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। तृणमूल ने बिरला को दो दिनों की मोहलत देने की पैरोकारी करते हुए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर करने से परहेज किया। बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को आगे की प्रक्रिया के लिए लोकसभा सचिवालय को भेज दिया है। साथ ही फैसला किया है कि वह अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया खत्म होने तक सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं करेंगे। इसी के अनुरूप वह मंगलवार को बजट चर्चा के दौरान आसन पर नहीं बैठे।

अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के साथ ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलने देने के विवाद ने नया रूप ले लिया है। सदन में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई, मुख्य सचेतक के. सुरेश, सचेतक मोहम्मद जावेद के साथ द्रमुक, सपा, शिवसेना यूबीटी जैसे विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को संविधान के अनुच्छेद-94सी के तहत बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का यह नोटिस मंगलवार दोपहर को सौंपा। नोटिस में अविश्वास प्रस्ताव लाने के चार कारण बताए गए हैं। पहला, वह खुलेआम सदन का एकतरफा ढंग से संचालन करते हैं और कई मौकों पर विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने नहीं दिया गया जो संसद में उनका बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है। इसमें दो फरवरी को राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल को नहीं बोलने देने का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है बल्कि नेता प्रतिपक्ष को लगभग हमेशा ही बोलने नहीं दिया जाता। आठ विपक्षी सांसदों का तीन फरवरी को बजट सत्र से 'मनमाने तरीके से निलंबन' की दूसरी वजह बताते हुए कहा गया है कि इन सदस्यों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए सजा दी जा रही है। तीसरा कारण चार फरवरी को एक भाजपा सांसद को दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के विरुद्ध बेहद आपत्तिजनक निजी हमले करने की अनुमति देना बताया गया है, लेकिन स्थापित संसदीय परंपराओं व नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए आसन से एक बार भी सांसद को फटकार नहीं लगाई गई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को ऐसी छूट पर आपत्ति करते हुए विपक्ष ने आरोप लगाया है कि आग्रह के बावजूद उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। विपक्षी महिला सांसदों द्वारा सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमले की तैयारी के आरोप को झूठा बताते हुए नोटिस की चौथी वजह बताया गया है। बिरला की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए नोटिस में कहा गया है, 'यह कांग्रेस सदस्यों पर साफ तौर पर झूठे आरोप लगाती हैं और अपमानजनक है।'

लोकसभा में टूटा गतिरोध, बजट पर चर्चा शुरू पेज>>3

पूर्व में तीन स्पीकरों के विरुद्ध आ चुका है अविश्वास प्रस्ताव

पूर्व में तीन लोकसभा अध्यक्षों- जीवी मावलंकर (1954), हुकुम सिंह (1966) और बलराम जाखड़ (1987) के विरुद्ध भी विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, मगर तीनों ही बार यह सरकार के बहुमत होने के कारण खारिज हो गया था।

राहुल ने नहीं किए हस्ताक्षर

अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर राहुल के हस्ताक्षर नहीं है। इस संबंध में कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि संसदीय मर्यादा का ध्यान रखते हुए स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सपा के कई सांसदों के हस्ताक्षर हैं जिनमें डिंपल यादव भी शामिल हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने हस्ताक्षर करने से परहेज किया है।

...तो सौंप दिया नोटिस

कांग्रेस के अनुसार, नोटिस देने से पूर्व कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विपक्षी दलों की बैठक के बाद बिरला से मुलाकात करके टकराव टालने का अंतिम प्रयास किया, मगर स्पीकर ने बजट चर्चा से पूर्व राहुल को बोलने देने की विपक्ष की मांग स्वीकार नहीं की तो दोपहर सवा बजे अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंप दिया गया।

अविश्वास प्रस्ताव पर अब आगे क्या

नियमों के अनुसार, लोकसभा सचिवालय अब अविश्वास प्रस्ताव नोटिस का परीक्षण करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने प्रेट्र को बताया कि नोटिस नियमानुसार पाए जाने पर डिप्टी स्पीकर इसकी भाषा की जांच करते हैं। यह अपमाननापूर्ण नहीं होनी चाहिए। चूंकि वर्तमान लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं है, लिहाजा इसकी जांच पीठासीन अधिकारियों में वरिष्ठतम सदस्य कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्ताव को 14 दिन बाद ही सदन में रखा जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के विचाराधीन होने के दौरान और इसके निष्पादन तक स्पीकर सदन के आसन पर नहीं बैठ सकते। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्ताव को विचार के लिए सदन में रखने पर अगर 50 सदस्य इसका समर्थन करते हैं तो प्रस्ताव पर चर्चा होती है। लेकिन 10 दिनों के भीतर इसका निष्पादन होना चाहिए। इस दौरान संविधान के अनुच्छेद-96 के तहत स्पीकर को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में बहुमत सदन के सदस्यों की कुल संख्या (रिक्तियों को छोड़कर) के आधार पर तय होता है, उपस्थित सदस्यों के आधार पर नहीं। मतदान में स्पीकर खुद भी मतदान कर सकते हैं, लेकिन टाई होने की स्थिति में नहीं। लोकसभा में राजग के पास बहुमत है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव से बिरला की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। मगर इसकी वजह से संसद में कड़वाहट और टकराव कहीं अधिक तीखा होगा। सचिवालय सूत्रों ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव पर नौ मार्च को चर्चा हो सकती है। इसी दिन वर्तमान बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी।

लोकसभा में टूटा गतिरोध, बजट पर चर्चा शुरू

विमर्श में अपने-अपने मुद्दे ▸ बजट के आंकड़ों के साथ ही अमेरिका से व्यापारिक समझौता भी बहस के केंद्र में रहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कई दिनों के हंगामे और बार-बार के स्थगन के बाद आखिरकार मंगलवार को लोकसभा में सत्तापक्ष-विपक्ष के बीच गतिरोध टूटा और बजट पर विमर्श शुरू हुआ। दो बार के स्थगन के बाद जब कार्यवाही दोपहर दो बजे शुरू हुई तो साफ हो गया कि चर्चा केवल बजट के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की स्थिति और अमेरिका से व्यापारिक समझौते जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी तीखा टकराव दिखेगा। चालू सत्र के प्रारंभ से ही दोनों पक्षों में टकराव जारी था, जिसके चलते राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी विमर्श नहीं हो पाया था।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चर्चा की शुरुआत करते हुए बजट को आम आदमी से कटा हुआ बताया। कहा- इसमें बेरोजगारी, बढ़ती असमानता और रहन-सहन की बढ़ती लागत को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में गालिब के शेर का हवाला देते हुए सरकार पर कटाक्ष किया कि यह बजट लोगों को केवल सुरक्षित होने का भ्रम देता है, ठीक वैसे ही जैसे कार में एयरबैग को इधर-उधर कर दिया जाए। साथ ही कहा कि किसानों की आय दोगुनी होने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है और सरकार को किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ानी चाहिए।

थरूर ने ट्रेड डील को लेकर भी सवाल उठाए और विदेश मंत्री व वाणिज्य मंत्री पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद को समझौते के दायित्वों की पूरी जानकारी नहीं दी गई, जबकि बजट के कई अनुमान इन्हीं पर निर्भर करते हैं।

तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने सरकार पर करों के बोझ को लेकर निशाना साधा और कहा कि मौजूदा व्यवस्था में जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक हर चीज पर टैक्स देना पड़ रहा है।

...इसलिए राहुल ने शुरू नहीं की चर्चा : कांग्रेस सूत्रों के अनुसार विपक्ष के कई नेता चाहते थे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बजट पर चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा करने से सत्तापक्ष की ओर से 'सुनियोजित व्यवधान' पैदा किया जा सकता है और इससे इस महत्वपूर्ण बहस चर्चा पर असर पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी बुधवार को केंद्रीय बजट पर बोल सकते हैं।

लोकसभा में मंगलवार को बोलते कांग्रेस सदस्य शशि थरूर। एएनआइ

- थरूर ने शुरू की चर्चा, कहा- बजट आम आदमी से कटा हुआ, किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाए
- टीएमसी के अभिषेक बनर्जी बोले- जनता को जन्म से लेकर मरने तक पर देना पड़ रहा टैक्स

लोकसभा में मंगलवार को बोलते तृणमूल सदस्य अभिषेक बनर्जी। एएनआइ

सरकार पर हमलावर अखिलेश बोले- अमेरिका से व्यापार समझौता डील नहीं बल्कि ढील

लोस में बोलते अखिलेश यादव। एएनआइ

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर लोकसभा में चर्चा के दौरान अमेरिका से कारोबारी समझौते को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह 'डील' नहीं 'ढील' है और इससे किसानों और घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ऐसा ही समझौता करना था तो 11 महीने का इंतजार क्यों कराया गया? उन्होंने बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि इसमें किसानों, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए ठोस प्रविधान नहीं दिखते।

2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में बजट निर्णायक कदम : अपराजिता सारंगी

विपक्ष की आलोचनाओं के जवाब में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बजट का जोरदार बचाव किया। उन्होंने कहा कि बजट 2026 व्यावहारिक, जनहितैषी और संतुलित है। उन्होंने इसे 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक और निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट सरकार की निरंतरता, संकल्प और जन-केंद्रित सोच को दर्शाता है और भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य के रूप में स्थापित कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया में चौथी सबसे बड़ी आर्थिकी हो गई है और यह जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी बनने की ओर अग्रसर है। देश में बेरोजगारी कम हुई है और यह केवल 4.8 प्रतिशत पर है, जबकि महंगाई पिछले एक दशक की तुलना में अपने सबसे निचले स्तर पर है।

लोस में बोलतीं भाजपा सदस्य अपराजिता सारंगी। एएनआइ

शाह बोले

साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से निपटने और इसके इकोसिस्टम को ध्वस्त करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यों को 1930 हेल्पलाइन पर पर्याप्त संख्या में कालर बैठाने को कहा

साइबर अपराधियों से निपटने के लिए एजेंसियों में समन्वय जरूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया है। शाह के अनुसार, साइबर फ्राड अब एक संगठित अपराध का रूप धारण कर चुका है। इससे सभी को मिलकर निपटना होगा। बड़ी संख्या सिम कार्ड, आइएमइआइ नंबर ब्लाक कराने से लेकर साइबर अपराधियों द्वारा ठगी गई रकम को वापस कराने में मिल रही सफलता का हवाला देते हुए उन्होंने राज्यों को हेल्पलाइन नंबर 1930 के लिए पर्याप्त कालर बैठाने को कहा, ताकि समय पर कार्रवाई से फ्राड की रकम तत्काल फ्रीज की जा सके।

साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से निपटने और इसके इकोसिस्टम को ध्वस्त करने पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने एक ओर तेजी से बढ़ते साइबर फ्राड के आंकड़े दिए तो वहीं उससे निपटने के लिए एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की।

शाह ने बताया कि 20 हजार करोड़ रुपये के साइबर फ्राड के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 8,189 करोड़ रुपये फ्रीज करने या पीड़ित को लौटाने में सफलता मिली है। इसी तरह गृह मंत्रालय ने 12 लाख सिम कार्ड को रद और तीन लाख मोबाइल के आइएमईआइ को ब्लाक करने के साथ ही 20,853 आरोपितों को गिरफ्तार भी किया है।

उन्होंने कहा कि 2021 में स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आइ4सी) ने देशभर की एजेंसियों के साथ समन्वय और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में प्रभावी कदम उठाया है। देश के 62 बैंक और वित्तीय संस्थाएं समेत 795 संस्थान आइ4सी के साथ जुड़ चुके हैं। इस साल के अंत तक सहकारी बैंकों समेत सभी वित्तीय एजेंसियों को इससे जोड़ दिया जाएगा।

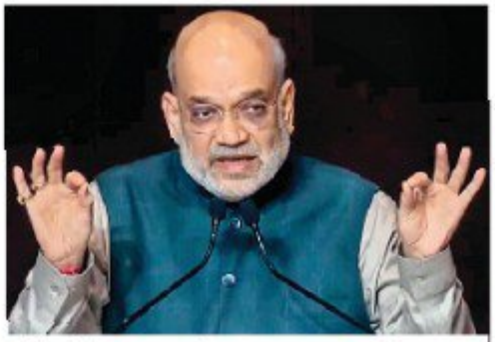

नई दिल्ली में मंगलवार को साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से निपटने और इसके इकोसिस्टम को ध्वस्त करने संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

देश में हर घंटे लगभग 100 व्यक्ति हो रहे हैं साइबर अपराध का शिकार

शाह ने आंकड़े पेश करते हुए साइबर अपराध की व्यापकता बताई। उनके अनुसार, देश में हर 37 सेकेंड में एक व्यक्ति यानी हर घंटे लगभग 100 व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए काफी कुछ किया गया है, लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। यदि हमने समय पर कदम नहीं उठाया होता तो साइबर अपराध साधारण अपराध के बजाय एक राष्ट्रीय संकट बन जाता। उन्होंने बैंकों से एनपीए की तरह ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की और आरबीआइ द्वारा बनाए गए म्यूल अकाउंट हंटर साफ्टवेयर का तुरंत अपनाने को कहा ताकि बैंकों के सभी खातों में से साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट को खोजकर बंद किया जा सके। अमित शाह ने इस अवसर पर सीबीआइ में एक नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आइ4सी के राज्य अपराध समन्वय केंद्र (एस4सी) का शुभारंभ भी किया।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग है : इसरो प्रमुख

बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अमेरिका के योगदान को रेखांकित किया

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जन-केंद्रित और अनुप्रयोग-आधारित पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव वी. नारायणन ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि भारत का अंतरिक्ष सफर किसी देश से होड़ करने के लिए नहीं, बल्कि आम जनमानस के कल्याण के लिए शुरू हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग है। बेंगलुरु में आयोजित 'यूएस-इंडिया स्पेस बिजनेस फोरम' के उद्घाटन समारोह में उन्होंने भारत के छह दशक लंबे अंतरिक्ष सफर की उपलब्धियों और भविष्य के लक्ष्यों को साझा किया। उन्होंने दोहराया कि अंतरिक्ष पूरी वैश्विक बिरादरी के लिए साझा स्थान है और इसका लाभ दुनिया के हर नागरिक को मिलना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने निरंतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और निजी भागीदारी का आह्वान किया।

बेंगलुरु में मंगलवार को 'यूएस-इंडिया स्पेस बिजनेस फोरम' के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते इसरो प्रमुख वी. नारायणन। प्रेट्र

जन-केंद्रित दृष्टिकोण और शुरुआती सहयोग: इसरो प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम हमेशा से अनुप्रयोग आधारित और जन-केंद्रित रहा है। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को याद करते हुए बताया कि भारत का पहला राकेट 1963 में अमेरिका द्वारा निर्मित था और उसे नासा ने ही उपलब्ध कराया था। नारायणन ने कहा, ""भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किसी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी के लाभ के लिए उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लाने के उद्देश्य से की गई थी। आज यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक समुदाय की सेवा कर रहा है।""

भविष्य का रोडमैप: 2040 तक चंद्रमा पर मानव

नारायणन ने इसरो के भविष्य के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का खाका भी पेश किया। कहा, भारत अपनी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। भारत 2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन का पहला माड्यूल लांच करने व 2035 तक पूर्ण बहु-माड्यूल स्टेशन संचालित करने का लक्ष्य रखता है। 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य तय किया है। 1980 में भारत का पहला प्रक्षेपण यान पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) में 35 किलो भार उठा सका था। अब इसरो 30 हजार किलो क्षमता वाले 'नेक्स्ट-जेनरेशन लांच व्हीकल' पर काम कर रहा है। चंद्रमा पर मानव भेजने के लिए 80-100 टन क्षमता वाले राकेटों की जरूरत होगी।

भारत-अमेरिका साझेदारी: समान स्तर का सहयोग: फोरम में मौजूद 14 अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों व प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा, भारत-अमेरिका के संबंध अब 'समान स्तर की साझेदारी' में बदल चुके हैं। उन्होंने चंद्रयान मिशनों का जिक्र करते हुए इसे तकनीकी नहीं, बल्कि 'भावनात्मक सहयोग' बताया।

एआइ के खतरों से सावधान रहें

अजय कुमार

एआइ के मामले में ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि मानव ही मशीन की तरह व्यवहार करने लग जाए

अवधेश राजपूत

पिछले एक दशक के दौरान दुनिया जितनी तेजी से बदली है, उसे देखते हुए अगले दस-बीस वर्षों के संभावित परिवर्तनों की थाह लेना आवश्यक हो गया है। मानव इतिहास के अधिकांश दौर में अभाव जैसे पहलू ने ही सभ्यताओं का तानाबाना रचा है। फिर चाहे यह खानपान का अभाव हो, जमीन, श्रम, पूंजी या कालांतर में ज्ञान का। हमारे आर्थिक सिद्धांतों का उद्भव एवं राजनीतिक संस्थानों का विकास भी अभाव प्रबंधन पर केंद्रित रहा। मशीनी कौशल यानी एआइ में इस पारंपरिक परिदृश्य को पलटने की क्षमता है। यदि बीसवीं सदी अभावों से पार पाने से जुड़ी थी तो आने वाला दशक अधिशेष के साथ संतुलन की चुनौती के नाम हो सकता है। नए परिदृश्य में तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उस लिहाज से हमारी संस्थाएं पिछड़ती जा रही हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि उन नीतिगत उपायों पर विचार किया जाए जो एआइ की उथल-पुथल से निपटने में कारगर साबित हो सकें।

पारंपरिक अर्थशास्त्र में उत्पादन के चार प्रमुख कारक-श्रम, पूंजी, भूमि और तकनीक माने गए हैं। तकनीक ने हमेशा श्रम को सहयोग प्रदान किया है। प्रत्येक तकनीकी संक्रमण उत्पादकता एवं पारिश्रमिक बढ़ाने के साथ ही मांग के विस्तार और नई नौकरियों का माध्यम बना है। इससे कुछ असुविधा होती भी थी तो बस तात्कालिक ही न कि स्थायी, मगर एआइ से यह रुझान पलट सकता है। पहली बार तकनीक सीधे तौर पर श्रम को प्रतिस्थापित करती दिख रही है। न केवल शारीरिक श्रम, बल्कि बौद्धिक, पेशेवर और रचनात्मक कामकाज के मामले में भी एआइ प्रभुत्व दिखा रही है। एआइ के साथ उत्पादकता तो बढ़ रही है, पर रोजगार सृजन उस हिसाब से नहीं हो रहा है। इससे साझा समृद्धि की राह प्रशस्त होने से रही। यानी विषमता बढ़ेगी। प्रकृति और स्वरूप में भी एआइ पिछली तकनीकों की तुलना में अलग है। इसका कोई प्रतिरूप एक बार आकार लेने पर यह सीमांत लागत को शून्य तक करने में सक्षम है। यह स्वाभाविक रूप से एकाधिकार की स्थिति निर्मित करता है। कुछ देशों की चुनिंदा कंपनियों द्वारा विशेष प्रतिरूपों में महारत हासिल करने से यह झलकता भी है।

तमाम विश्लेषकों को आशंका सता रही है कि एआइ बड़े स्तर पर हलचल मचा सकती है। यह मानव समाज के संतुलन को भी प्रभावित करने में सक्षम है। आज उत्पादकता और क्षमताएं निरंतर बढ़ रही हैं। वस्तुएं सस्ती हो रही हैं। सेवाओं का स्तर सुधरा है। जीवन प्रत्याशा बढ़ी है और बीमारियों पर बोझ घट रहा है। जीवन के विस्तार और काम का दायरा सिकुड़ने पर जननांकीय लाभांश अपने अर्थ खो देता है। इस परिदृश्य में विदेश से भेजी जाने वाली धनराशि पर निर्भर राष्ट्र-समाज समस्याओं का सामना करते हैं। तब गरिमा और आजीविका के आधार के रूप में रोजगार का विचार संकट का शिकार होने लगता है।

संसाधनों का संकेंद्रण भी एआइ के मोर्चे पर पैदा होने वाली एक और समस्या है। ऐसे में संसाधनों के पुनर्वितरण के लिए कोई कारगर नीतिगत उपाय खोजना ही होगा। इसके अभाव में व्यापक आर्थिक दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। एआइ के चलते सीखने-समझने की क्षमताओं पर भी संकट मंडराता दिख रहा है। जब मशीन ही फैसले लेने में भूमिका निभाने लगेगी तो लोगों में सीखने के प्रति झुकाव घटने का अंदेशा बढ़ता है। इतिहासकार डेविड रोकलिन ने यह रेखांकित भी किया था कि आटो-पायलट मोड पर अत्यधिक निर्भरता संकट के समय पायलटों के हाथ-पांव फुला देती है। बड़ा खतरा यह नहीं कि मशीन किसी इंसान की भांति काम करे, बल्कि यह खतरा कहीं विकराल होगा कि इंसान ही मशीन की तरह व्यवहार करने लगे।

एआइ की वजह से फर्जी सूचनाओं और तमाम संदिग्ध सामग्री का सैलाब भी संकट बढ़ा रहा है। इससे भरोसे की भावना पर आघात पहुंचा है। सत्य और मिथ्या को लेकर ऐसा जाल बुना जा रहा है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं। एआइ पर पकड़ रखने वाले और ताकतवर बनने की राह पर हैं। इसके दम पर नव-धनकुबेरों का उभार हो रहा है।

भू-राजनीतिक संदर्भ में भी एआइ विषमता बढ़ा रही है, क्योंकि आधुनिक तकनीक से वंचित देश स्वतः पिछड़ते जाएंगे। किसी देश की संप्रभुता पर किसी अन्य देश से संचालित हो रहे एल्गोरिदम से ग्रहण लग सकता है। इस सबके बावजूद अगर सही नीतिगत उपाय किए जाएं तो एआइ बहुत सकारात्मक परिवर्तन भी कर सकती है। इसके लिए एआइ को तकनीकी उपकरण से अधिक सभ्यतागत शक्ति के रूप में देखना होगा। एआइ का उपयोग मानव की जगह लेने के बजाय उसकी क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। एआइ उन तमाम समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, जिसके लिए असाधारण मानवीय प्रयासों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि बाहरी-अंतरिक्ष में कोई नया मोर्चा खोलना, गहरे समुद्र या पृथ्वी की जटिल परतों के रहस्यों को सुलझाना। इससे कई ग्रहों पर मानवीय जीवन को संभव बनाया जा सकता है। हम प्रकृति को बेहतर तरीके से समझकर उसके कुशल प्रबंधन के मंत्र समझ सकते हैं। तथ्यों एवं सूचनाओं के सत्यापन के लिए भी इसकी सेवा कारगर होगी।

यह स्वीकारने में कोई संदेह नहीं कि एआइ कितनी भी क्षमताएं अर्जित कर ले, लेकिन उसका प्यार, देखभाल, समानुभूति और नैतिक दायित्वों जैसी मानवीय भावनाओं से युक्त होना संभव नहीं है। एआइ से मरीज का उपचार भले ही बेहतर हो जाए, लेकिन प्यार-दुलार और देखभाल प्रियजनों से ही संभव है। हमें समझना होगा कि एआइ कोई प्रतिस्पर्धी लाभ नहीं, बल्कि एक साझा दायित्व है। वसुधैव कुटुंबकम् का भारतीय विचार अब दर्शन के दायरे से निकलकर अस्तित्व की रणनीति का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में, भारत अपनी सभ्यतागत गहराई और विश्वसनीयता के माध्यम से नए शासकीय ढांचों के लिए वैश्विक एआइ मानदंडों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

(लेखक पूर्व रक्षा सचिव एवं यूपीएससी के चेयरमैन हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)
response@jagran.com

Centre prescribes labels for all photorealistic AI content online

Amended rules require disclosure for AI-generated media, warn platforms of loss of safe harbour for non-compliance; new changes take effect on February 20; shorter timelines to social media companies for takedown of illegal, sensitive content

Aroon Deep
NEW DELHI

The Union government has notified amendments to the Information Technology Act, 2021, requiring photorealistic AI-generated content to be prominently labelled.

The changes, which will come into force on February 20, also significantly shorten timelines for takedown of illegal material.

Under the new rules, social media platforms will now have between two and three hours to remove certain categories of unlawful content, a sharp reduction from the earlier 24-36 hours.

Content deemed illegal by a court or an "appropriate government" will have to be taken down within three hours, while sensitive content, featuring non-consensual nudity and deepfakes, must be removed within two hours.

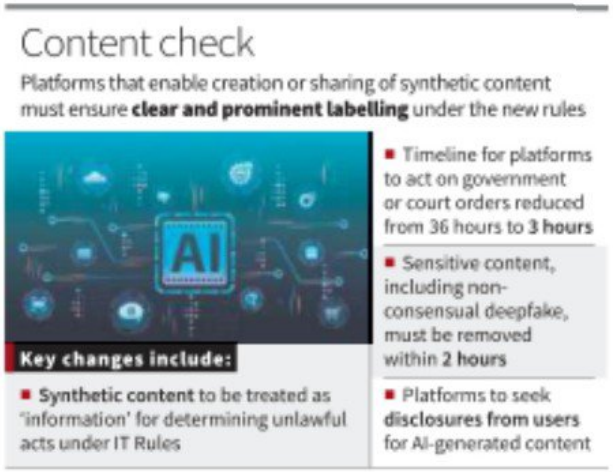

The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2026, defines synthetically generated content as "audio, visual or audio-visual information which is artificially or algorithmically created, generated, modified or altered using a computer resource, in a manner that such information appears to be real, authentic or true and depicts or portrays any individual or event in a manner that is, or is likely to be perceived as indistinguishable from a natural person or a real-world event."

The final definition is narrower than the one released in a draft version of these rules in October 2025. As with the existing IT Rules, failure to comply with the rules could result in loss of safe harbour, the legal principle that sites allowing users to post content cannot automatically be held liable in the same way as a publisher of a book or a periodical can.

Proactive labelling

Platforms will be required to seek disclosures from users in case their content is AI-generated. If such a disclosure is not received for synthetically generated content, the official said, firms would either have to proactively label the content or take it down in cases of non-consensual deepfakes.

The amended rules mandate that AI-generated imagery be labelled "prominently". While the draft version specified that 10% of any imagery would have to be covered with such a disclosure, platforms have been given some more leeway, the official said, since they pushed back on such a specific mandate.

"Provided that where [a social media] intermediary becomes aware, or it is otherwise established, that the intermediary knowingly permitted, promoted, or failed to act upon such synthetically generated information in contravention of these rules, such intermediary shall be deemed to have failed to exercise due diligence under this sub-rule," the rules say, hinting at a loss of safe harbour.

The rules also partially roll back an amendment notified in October 2025, which had limited each State to designating a single officer authorised to issue takedown orders. States may now notify more than one such officer– an "administrative" measure to address the need of States with large populations, the official said.

Opposition MPs submit notice seeking removal of Om Birla as LS Speaker

Sandeep Phukan
Sobhana K. Nair
NEW DELHI

Opposition parties belonging to the Indian National Developmental, Inclusive Alliance (INDIA) on Tuesday submitted a notice to the Secretary-General of the Lok Sabha, seeking the removal of Speaker Om Birla for allegedly conducting the business of the House in a "blatantly partisan" manner.

The notice to bring a resolution for the removal of the Speaker cited four specific reasons, including not allowing Leader of the Opposition Rahul Gandhi to complete his speech on the Motion of Thanks to the President on February 2.

"This is not an isolated instance. The Leader of the Opposition in the Lok Sabha is almost invariably not allowed to speak," the notice said. The notice, with nearly 120 signatures, was submitted to Lok Sabha Secretary-General Utpal Kumar Singh by Congress chief whip K. Suresh and whip Mohamed Jawed on behalf of several Opposition parties, including the Congress, Samajwadi Party, and Dravida Munnetra Kazhagam (DMK). However, the Trinamool Congress did not sign the notice.

Soon after the submission of the notice against the Speaker, the Opposition agreed to let the House function.

The discussion on the Budget started in the second half of the day. Mr. Gandhi is likely to take part in the discussions tomorrow.

Mr. Birla has directed the Secretary-General to take appropriate action of "examining and processing" the notice, according to the rules, sources said.

At least two Lok Sabha members have to sign the notice to move a resolution for the removal of the Speaker and a minimum of 14 days' notice has to be given before the resolution can be taken up by the House.

Under Article 94C of the Constitution, the Speaker can be removed from office by a resolution passed by the House through a simple majority. Article 96 of the Constitution allows the Speaker to respond to the notice for removal but the charges against her/him will have to be specific.

Big move: Congress leaders Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi with floor leaders of INDIA bloc parties in New Delhi on Tuesday. ANI

"We, the undersigned, hereby give notice of a resolution for the removal of Shri Om Birla from the office of Speaker Lok Sabha, in terms of the provisions of Article 94(c) of the Constitution of India, because of the blatantly partisan manner in which he has been conducting the business of the Lok Sabha," the notice said. "On several occasions, leaders of Opposition parties have just not been allowed to speak, which is their basic democratic right in Parliament."

'Arbitrary suspension'

Apart from Mr. Gandhi's speech, the notice said that on February 3, eight Opposition MPs were "arbitrarily suspended" for the entire Budget session and were "being penalised merely for exercising their democratic rights".

On February 4, a BJP MP was permitted to make "wholly objectionable and personalised attacks" against two former Prime Ministers, without being reprimanded even once for disregarding established conventions and norms of propriety, the notice said, referring to Nishikant Dubey's remarks.

"In spite of our request, no action has been taken against this particular MP, who is a habitual offender," it said.

Referring to the Speaker's statement that he had "concrete information" that Congress members might move towards Prime Minister Narendra Modi's seat and carry out "some unexpected act", the notice termed these remarks "blatantly false allegations" and his decision to make these observations from his Chair as "indicative of an abuse of this constitutional office".

"While we hold the Speaker, Lok Sabha, in personal regard, we are pained and anguished at the manner in which he has consistently prevented opposition members of Parliament from raising issues of legitimate public concern," the notice said.

WON'T CHAIR HOUSE: BIRLA
» PAGE 5

Global warming and pollution are stripping vibrant colours from nature

Climate change is turning seas greener, forests browner and coral reefs whiter; as habitats grow warmer and more polluted, insects and birds are altering their pigmentation, reshaping how they adapt to their surroundings, tolerate heat and even how successfully they mate

Nivedita S.
CHENNAI

The colours of the natural world are not what they once were. More than half of the oceans have become greener over the last 20 years, and forests are turning brown prematurely. Various species of flora and fauna have also been changing their colours to adapt to rising temperatures, loss of habitats, and pollution.

This ecological discoloration is a direct consequence of climate change.

Living creatures are coloured a certain way for their survival and reproductive needs. Colours help escape predators, attract mates, and manage heat, among other functions.

A study published in *Biodiversity and Conservation* found that rising deforestation in the Amazon is causing butterflies to lose their bright displays. Butterflies in areas with human disturbance also sported a less diverse palette on the wings than those in the deeper, untouched parts of the forest. The researchers also found that areas with large-scale deforestation lacked the most colourful butterflies: less bright butterflies were able to camouflage better to escape predators and adapt to the loss of natural vegetation.

Becoming lighter

These changes echo one during the Industrial Revolution, when engine smoke and soot darkened the barks of trees and rendered the natural camouflage of lighter peppered moths ineffective. Over time, the darker peppered moths – which used to be rare – became more common in urban areas.

"In theory, the main adaptive pattern of colour change in relation to global warming would be a reduction in the deposition of melanin pigments," Kaspar Delhey, an ornithologist at the Monash University, told *The Hindu*.

Eumelanin produces dark brown/black shades and pheomelanin produces yellow and red hues. They are the two main types of melanin pigments in animals. When their bodies produce less melanin, they become lighter.

In a 2024 study in *Ecology and Evolution*, scientists also reported that several insects, including ladybirds and dragonflies, in the temperate northern hemisphere are turning lighter due to frequent heatwaves.

"Colour changes can have clear thermoregulatory benefits: lighter colour under warmer conditions can prevent overheating and allow insects to remain active for longer periods, while darker insects heat up faster in colder regions," Md Tangigul Haque, researcher at Macquarie University and one of the authors of the study, said.

Grim shades: Coral bleaching seen in formations along the Great Barrier Reef off Australia. AFP

The finding is in line with Bogert's rule: that animals in colder regions will be darker and those in warmer regions will be lighter. It is mainly applicable to cold-blooded animals. On the other hand, Gloger's rule applies to warm-blooded creatures, saying animals are darker in areas with high humidity and rainfall and lighter in colder, drier regions.

In a 2024 study in *Molecular Ecology*, scientists found that, thanks to milder winters, the brown morph of the tawny owl was found to be more dominant than the grey one in Europe. This was because the darker colour protected better against UV radiation.

Aside from climate change, rapid urbanisation and pollution are changing colours in the wild. In a 2024 study of 547 bird species in China, scientists found those in cities were darker and duller while rural areas abounded (relatively) in the more colourful birds. The authors speculated that heavy metals like lead could bind with melanin to produce darker plumage in urban areas.

Changes in pigments of plants also affect animals. Carotenoids afford plants red, yellow, and orange hues, and draw animals to consume them. Scientists have noticed that urban plants produce this pigment less. A 2020 study in *Current Biology* reported that flowers were altering their UV-related pigments to prevent being damaged by sunlight. These pigments are not visible to the human eye; they are intended for pollinators instead, and by changing them the plants could become less 'attractive'.

"Colour changes that improve survival might reduce mating success or involve other fitness costs," Dr. Haque said. This affects reproduction in particular, with animals shifting their courtship timing to cooler periods, he added.

The changes echo one during the Industrial Revolution, when engine smoke and soot darkened the barks of trees and rendered the natural camouflage of lighter peppered moths ineffective, leading to the darker peppered, moths, which used to be rare, becoming more common

'Underwater forest'

A striking example of ecological discolouration in India is underwater. In February 2025, scientists reported coral bleaching events in the Gulf of Mannar, Palk Bay, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, and the Gulf of Kachchh. When corals suffer heat stress, they expel symbiotic algae and turn white. Such bleached corals face a higher risk of starvation and disease.

"A healthy coral reef is like an underwater forest," Thinesh T., assistant professor at Sultan Qaboos University in Oman and one of the authors of the study, said. "When corals bleach or die, reefs lose their complex structure that provides shelter and breeding areas for many marine organisms. Fish and invertebrate populations decline, while algae and other stress-tolerant organisms often take over. This reduces biodiversity and disrupts the balance of the marine ecosystem."

A burgeoning population of algae is also rendering the oceans greener.

"Algal blooms can reduce water clarity and block sunlight, making it harder for corals and seagrasses to photosynthesise. When blooms die and decompose, they can also lower oxygen levels in the water, harming fish and other marine life," Dr. Thinesh said.

A positive effect

Given the cascading effects of colours, minimising their change has become an important thrust of climate action. However, experts have flagged a large knowledge gap thanks to a lack of studies in the southern hemisphere and tropical areas and that large geographic surveys are required to establish the current trends.

"By successfully implementing strategies from both field- and lab-based monitoring, we can guide interventions; for example, preserving microhabitats such as shaded areas may help dark-coloured insects avoid overheating," Dr. Haque said.

On the bright side, the study in the Amazon also found that forest areas that had regenerated naturally had a positive effect on the colours of butterfly species. In India, experts have said, regulating coastal development, improving water quality, and tracking stress indicators will minimise coral bleaching. Put another way, it is still not too late to restore the world its true colours.

(nivedita.s@thehindu.co.in)

THE GIST

- Aside from climate change, rapid urbanisation and pollution are changing colours in the wild
- A 2024 study in *Ecology and Evolution* reported that several insects, including ladybirds and dragonflies, in the temperate northern hemisphere are turning lighter due to frequent heatwaves
- A striking example of ecological discolouration in India is underwater, where coral bleaching events are posing an existential threat to a vibrant ecosystem
- On the bright side, a study in the Amazon found that forest areas that had regenerated naturally had a positive effect on the colours of butterfly species

The approaching AI surge, its global consequences

M.K. Narayanan

is a former Director, Intelligence Bureau, a former National Security Adviser, and a former Governor of West Bengal

If there is a single technology that promises to unravel the present and usher in a new era, the bet would be on Artificial Intelligence (AI). At the very least, AI is set to effect a transformation that is comparable to any previous revolution, not excluding the Industrial Revolution. Impressive Large Language Models (LLMs) are already rolling out faster than one would have imagined possible. Rivalry between the United States and China in this area has become intense and the success of recent Chinese models is having a catalytic effect on the AI industry as a whole. This is, however, only the beginning.

All this has special relevance to a world which Canadian Prime Minister, Mark Carney, described in his address to the World Economic Forum (WEF) in Davos (in January this year), as follows: "... We are in the midst of a rupture, not a transition... great powers have begun using economic integration as weapons, tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited". Mr. Carney did not, however, touch on potentially the greatest disruptor of all, *viz.*, AI, or refer to the baneful/beneficial influence of AI which is already beginning to impact today's world. When he talked of great power rivalry, and that countries in between have a choice, there was no mention of AI and what impact it would have on today's world, and more so in the future.

Face the reality

World leaders must, however, wake up to this new reality, and come to terms with a phenomenon in which Open AI is beginning to consume the world. There is little realisation that the transformation that is taking place is almost certain to turn the world upside down. When Mr. Carney stated that 'we are in the midst of a rupture and not a transition', he did not have in mind – and probably realised even less – that it is the advent of AI, rather than other aspects, that is likely to herald the collapse of the international order as we know it.

Few leaders currently understand the extent of the threat posed by AI to the world as we know it. Some industry leaders such as Microsoft CEO Satya Nadella have pointed out that AI was already being used as tools of diplomacy and state-craft, and that nations require to build resilience and sovereign stacks. AI did figure in discussions at the WEF, but the contents of the debate hardly mirrored the dangers arising from unchecked AI. A great deal of the debate turned on how countries were placed to exploit this new phenomenon, with Union Minister for Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnaw taking time off to rebut the presumption that India was a secondary AI power. Industry leaders, no doubt, increasingly see AI as a strategic enabler, given that digital transformation is helping to reshape competitiveness across different sectors – from fintech to health care. Additionally, there is some realisation that AI's potential extends to other sectors as well. The judicial fraternity, for one, however, believes that there is a need to be more cautious about the use of AI in court proceedings, and that excessive reliance on AI in court rooms could lead to misjudgment. They point to the dangers of 'hallucinations' which could lead to improper citations and fabricated judgments.

With AI disrupting global power, warfare and governance, the issue is whether humanity can keep pace with a set of checks and balances in place

Marching ahead across domains

All this, however, is but a precursor to what the real potential and danger posed by AI in the world of tomorrow are. As AI proliferates globally, it is already becoming evident that few technologies have the potential to exert the same degree of influence in terms of enhancing information flows, surveillance capabilities, revolutionising of communications, empowering analytical frameworks and the military-industrial segment. No other area of technology seems to have such a profound impact on existing civilisational networks.

In this sense, AI portends a breaching of certain limits that had existed since the Second World War and the overweening threat posed by technology and its utilisation in different domains. What is noteworthy is that AI operates at granular levels – and that the technology itself is undergoing a phased transition. In its present form, AI is already enabling the replication of speech and language, vision and reasoning, but what is little realised is that it is set to achieve new and dangerous heights of capabilities. This is specially so in regard to military and defence applications, for as AI becomes increasingly militarised, warfare itself is bound to – and is already undergoing – a paradigm shift from man to unmanned platforms, and from dependence on human-controlled systems to autonomous ones, that are capable of making their own decisions.

Even as AI is set to become all pervasive, its transformative impact on warfare, especially in the area of the evolution of weapon systems, is what is most worrisome. AI has made possible the deployment of unmanned aerial vehicles that are capable of autonomous flight. AI-driven cyber weapons and uncrewed ground vehicles equipped with intelligent navigation and targeting capabilities are already a reality. Both represent a paradigm shift in redefining combat, and employing operations across multiple systems without direct human intervention. As of today, AI offers unprecedented opportunities for the enhanced automation of operational decisions in areas of conflict, and of transforming battlefield dynamics.

Already, the portrayal of Ukrainian soldiers wearing night vision goggles, riding 'Quad bikes' to protect the capital city of Kiev, and launching 'jerry-rigged drones' equipped with small explosives, has become the defining image of future conflicts. Ukraine's success in checking and keeping at bay the mighty Russian Army in the first wave of Russia's attacks on Ukraine, employing the latest AI technology, marks the most fundamental change in tactics of warfare since the advent of tanks at the end of the First World War. Ukraine's response has demonstrated the value of 'coming age technology', and how their skilful use could undermine conventional military capabilities. It is the hugely asymmetric impact that AI commands, that is both its strength and its danger portent. Though this is not being openly mentioned or touted, the reality is that it represents a colossal transfer of power from the traditional military to others, who have the capacity to develop and utilise AI devices. The real danger is that AI could very soon eclipse the smartest individuals, and nobody can or will know, when they become autonomous, and totally out of human control.

The dystopian impact of a powerful set of technologies which are not under the control of a human body or entity, and of self-sustaining technology, portrays a doomsday scenario. The beginnings of this are already evident, and are set to escalate enormously to the next levels of the concentration of power. There are unlimited possibilities in the doomsday scenario of autonomous drone swarms unleashing attacks on crowds, killing hundreds, if not, thousands. Both the military and security establishments would seek to equip themselves with such devices in a few years. AI would then be well set to become the greatest force amplifier in history. Its impact could range from wars and accidents, to random terror groups, to counter-revolutionary forces, and the like. The blunt truth is that nobody knows when, if how, AI might overtake or eclipse humans, and become an autonomous force for good or evil.

It is also becoming evident that, apart from the battlefield, AI is now becoming an instrument of immense value in different spheres of human activity including diplomacy and intelligence. In that sense, it is no longer merely a tool. Concerns that technologies such as AI would outpace institutions meant to govern them are real, but the most spectacular demonstration of AI is as yet on the battlefield – as seen across western Europe and West Asia. In both sectors, space, cyber and electronic warfare capacities have been woven together to completely transform the nature of warfare itself.

Need for effective oversight

The *obiter dictum* – given that AI enables rapid data processing and predictive analysis, and also provides opportunities for a variety of options, including crisis response, conflict prevention, and conflict resolution – is that humankind must develop a set of checks and balances to prevent AI from 'running away with the bit in its mouth'. Scientists, political leaders and others must come together to understand the implications of runaway AI technologies and decide how to keep them under control and in a manner that they benefit, rather than become a threat to, humankind.

Changing priorities: The SpaceX headquarters in Hawthorne, California, U.S., on June 5, 2025. REUTERS

What explains SpaceX and Blue Origin stepping up their moon plans?

The simplest explanation for the pivot is that it improves the rate at which SpaceX can learn the technologies it most needs to mature. Another possibility is that in the current environment, lunar missions are also accompanied by external demand and more legible milestones

Vasudevan Mukunth

Two of the world's most visible private space companies are shifting their attention and resources to moon missions even as both continue to speak about longer term ambitions to Mars and beyond. For many years, the public identity of SpaceX has been fused with settling humans on Mars. Its founder and CEO Elon Musk has repeatedly argued that a self-sustaining settlement on Mars would reduce the risk if a catastrophe on the earth ends human civilisation. He and SpaceX have also presented the Starship programme as the transport system that could render large-scale interplanetary travel feasible.

Blue Origin, founded by billionaire Jeff Bezos, has projected a different long-term vision: of building industrial capacity in space so that heavy industry can move off the earth. In recent years, it has focused on developing its New Glenn heavy-lift rocket and a lunar lander for NASA's Artemis programme. It has also been flying customers on short suborbital trips aboard its New Shepard rocket.

What have the companies decided?

While SpaceX has also been central to NASA's Artemis plans to the moon, now, however, the company is describing the moon as its immediate next priority in its sequence of major goals. The company has reportedly told investors that it is targeting an uncrewed lunar landing by March 2027 and that Mr. Musk has decided to focus on building a "self-growing city" on the moon. He also said on X that this can be achieved in under 10 years even while claiming that plans for a Mars city could still follow in roughly five to seven years.

While the moon and Mars are both interplanetary bodies, missions to the former are easier for many reasons. The moon is under a week away by rocketflight; the distance is low enough for communications to be near-real-time; and the orbits of the earth and the moon are such that there are roughly three opportunities to launch to the moon every month. Going to Mars is much less forgiving. The most fuel-efficient launch opportunities come around roughly once every 26 months; the travel time is in months; and failing to get to the red planet on one attempt will mean a multi-year delay before the next comparable chance. Mr. Musk has in fact leaned into these differences to justify SpaceX pivoting to the moon.

To be noted is the fact that SpaceX is approaching an IPO and Mr. Musk has already merged it with xAI, another company he founded to use AI to advance "scientific discovery and gain a deeper understanding of our universe". So Mr. Musk's claims are being subjected to more scrutiny than before, with investors and the general public also on the watch for inflated promises and hype.

Late last month, Blue Origin also announced that it would hold its suborbital space tourism programme for at least two years and reallocate its resources to accelerating its "human lunar capabilities", including development work tied to the company's contract to build a lunar lander for NASA.

Why have they decided this?

In the U.S., NASA's priorities have become a political fight. Some leaders want it to fly to the moon first while others talk up Mars. When the U.S. Senate pressed NASA Administrator Jared Isaacman on whether pushing to go to Mars first would weaken the agency's moon programme, including Artemis, he replied that NASA could pursue both and tried to assure lawmakers that he supports the current moon plan and that he isn't taking directions from Elon Musk (SpaceX is one of NASA's biggest contractors. Mr. Isaacman has also flown twice on privately funded SpaceX missions that he organised and paid for, Inspiration4 and Polaris, which makes him both a customer and a high-profile partner of SpaceX. Mr. Musk had also pushed for Mr. Isaacman's nomination, and senators explicitly asked Mr. Isaacman whether he had discussed how he would run NASA with Mr. Musk. While he answered that he had not, the fact that this was asked in a confirmation hearing says the suspicion of undue influence existed).

The simplest explanation for the pivot is that it improves the rate at which SpaceX can learn the technologies it most needs to mature. Another possibility is that in the current environment, lunar missions are also accompanied by external demand and more legible milestones. Mr. Musk's remarks come as the competition between the U.S. and China to return humans to the moon has intensified. As a result, being able to go to the moon has become a marker of geopolitical leadership and, importantly, a top priority for NASA.

Blue Origin, on the other hand, has two big problems it needs to solve to get to the moon: it needs to prove it can execute such complex, human-rated systems and it needs a near-term programme with real deadlines and external accountability. And its contract to build a lunar lander for NASA gives it both. Moon work is also more politically tractable than suborbital tourism, and if it succeeds, Blue Origin can buy credibility with NASA and with the broader space community.

Shouldn't they have seen NASA's plans coming?

Curiously, NASA's focus vis-à-vis humans in space has been about getting to the moon first.

Should SpaceX and Blue Origin not have seen this coming instead of making a hard turn towards the moon within a month of each other?

Perhaps the surprise isn't that they both had plans for the moon but that they both kept centring their timelines and product narratives on getting humans to Mars for such a long time.

There's no need for public narratives to be the same as internal ones. SpaceX's brand has been built on getting to Mars and Mr. Musk has repeatedly used Mars dates as a way to signal the company's ambitions, to attract talent, and to keep public attention on Starship. Internally, however, the company has been deeply embedded in moon-related work thanks to NASA contracts. And now, SpaceX and Mr. Musk are aligning internal and external narratives and clarifying – or perhaps admitting – that the next major milestone is in fact a lunar landing, and that Mars will only come later. In other words, SpaceX and Blue Origin may have known the moon would be the next stop, just that they didn't want it to be the headline as well.

In sum, delays in NASA's Artemis schedule, tougher political oversight, and more geopolitical pressures have pushed NASA leaders to speak more loudly and more often about a moon-first agenda. Lawmakers in Congress, especially the Senate committees that authorise and fund NASA, have pressed Mr. Isaacman and other senior officials to defend the Artemis programme and explain how NASA will beat or match its international rivals, but especially China, in returning to the moon.

As that pressure increased, NASA could have signalled to its contractors that lunar milestones would define their success for now.